Prosecution Service — **Crown Counsel Policy Manual**

नीति: **ज़मानत - वयस्क**		
नीति कोड: **BAI 1**	प्रभावी होने का दिनांक: नवम्बर 22, 2022	पार-संदर्भ: CHA 1 CHI 1 GUI 1 IPV 1 SEX 1 VUL 1

अपराध के आरोप में प्रत्येक व्यक्ति को उचित शर्तों पर जमानत का मौलिक अधिकार है और उचित कारण के बिना उचित जमानत से इनकार नहीं करने का अधिकार है।

जमानत का अधिकार अटूट रूप से निर्दोषता की धारणा से जुड़ा हुआ है। कैनेडियन कानून मानता है कि एक आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जाएगी:

> *...आरोपी व्यक्तियों की रिहाई मुख्य नियम और निरोध, अपवाद है...स्वचालित रूप से निरोध का आदेश देना 'उचित ज़मानत पाने के मूल अधिकार के विपरीत होगा जब तक कि अन्यथा करने का कोई उचित कारण न हो'।*[1]

पूर्व-परीक्षण हिरासत आरोपी और उनके परिवार के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और केवल सुरक्षित रिहाई के लिए दोषी को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा जाना चाहिए। यहां तक कि जब अभियुक्त को हिरासत में हिरासत में नहीं लिया जाता है, तब भी रिहाई की अनावश्यक या अनुचित शर्तें किसी ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं जिसे निर्दोष माना जाता है और जो अन्यथा वैध व्यवहार को संभावित रूप से अपराधी बना सकता है।[2]

उचित ज़मानत के संवैधानिक अधिकार के बंधन के बावजूद, *अधिकारों और स्वतंत्रता के चार्टर*[3] के लागू होने के बाद से रिमांड आबादी और ज़मानत से इनकार में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। पहले से ही दबी हुई आपराधिक न्याय प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव से परे, रिमांड की आबादी में वृद्धि से वंचित और कमजोर समुदायों के आरोपी व्यक्तियों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है और अभियुक्त के अपराधीकरण के जोखिम को बढ़ाता है। यह कैनेडियन आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर मूल निवासियों के पहले से ही अस्वीकार्य अति-प्रतिनिधित्व को भी बढ़ा देता है।[4]

---

[1] *R v St-Cloud*, 2015 SCC 27 at para 70

[2] *R v Zora*, 2020 SCC 14 at para 25

[3] *R v Antic*, 2017 SCC 27 at para 64

[4] *R v Zora*, 2020 SCC 14 at para 79; Statistics Canada, "Adult and youth correctional statistics in Canada, 2018/2019", by Jameil Malakieh in Juristat Catalogue No 85-002-X (Ottawa: Statistics Canada, 2020) at 7, online < https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00016-eng.htm>

जमानत का विरोध करना है या सहमति देना है, और किन शर्तों पर, यह निर्णय लेने के लिए क्राउन काउंसल को अभियुक्तों, जनता और पीड़ितों के प्रतिस्पर्धी हितों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्राउन काउंसल निश्चित रूप से अभियुक्त के भविष्य के कार्यों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और इस प्रकार सभी जोखिमों को समाप्त नहीं कर सकता है। निर्दोषता की धारणा पर आधारित न्याय प्रणाली में यह अपरिहार्य है, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को उचित जमानत का मौलिक अधिकार है। ज़मानत की शर्तों का प्रस्ताव करते समय, क्राउन काउंसल को कथित अपराध की परिस्थितियों और सभी ज्ञात और यथोचित पूर्वाभास योग्य जोखिम कारकों को ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम प्रतिबंधात्मक ज़मानत शर्तों की मांग करनी चाहिए जो अभियुक्त द्वारा उत्पन्न जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक कम कर सकें।

न्याय प्रणाली को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, क्राउन काउंसल को ज़मानत के बारे में विवेकाधीन निर्णय लेने की आवश्यकता है। जैसा कि क्राउन काउंसल पॉलिसी मैनुअल के गाइडिंग प्रिंसिपल्स (GUI 1) में बताया गया है, जब क्राउन काउंसल इस नीति के अनुसार सैद्धांतिक निर्णय लेते हैं, परिणाम की परवाह किए बिना, बीसी प्रॉसिक्यूशन सर्विस और असिस्टेंट डिप्टी अटॉर्नी जनरल उनके फैसलों का समर्थन करेंगे।

सामान्य

कानूनी रूप से उचित होने के लिए, पूर्व-परीक्षण निरोध या आरोपी व्यक्ति की रिहाई पर रखी गई कोई भी शर्त *आपराधिक संहिता* की धारा 515(10) में वर्णित तीन उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए आवश्यक होनी चाहिए:

- अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए
- जनता की सुरक्षा या सुरक्षा के लिए, एक पीड़ित, या एक गवाह, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस बात की पर्याप्त संभावना शामिल है कि अभियुक्त हिरासत से रिहा होने पर, एक आपराधिक अपराध करेगा या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा
- न्याय के संचालन में विश्वास बनाए रखने के लिए

किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्री-ट्रायल हिरासत या जमानत की शर्तों की मांग करना कानूनी रूप से उचित नहीं है, जिसमें शामिल हैं: आरोपी को दंडित करना, आरोपी के अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य या लत के मुद्दों के उपचार को लागू करना, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करना, या प्रोत्साहित करना एक अभियुक्त को दोषी ठहराने या कोई अन्य रियायत या स्वीकार करने के लिए।[5]

क्रिमिनल कोड की धारा 515(10) में उल्लिखित वैधानिक आधारों के अलावा, जमानत पर क्राउन काउंसल की स्थिति को धारा 493.1[6] में संहिताबद्ध "संयम के सिद्धांत" द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। संयम के सिद्धांत के लिए एक न्यायाधीश को आरोपी की जल्द से जल्द उचित अवसर पर रिहाई पर प्राथमिक विचार

---

[5] *R v Zora*, 2020 SCC 14 at para 85

[6] *R v Zora*, 2020 SCC 14 at para 100

करने की आवश्यकता होती है, कम से कम कठिन शर्तों पर जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और अभियुक्तों के अनुपालन के लिए यथोचित व्यावहारिक हैं।

हालांकि, संयम के सिद्धांत की व्याख्या समग्र रूप से जमानत प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए और जब भी उचित हो, यह क्राउन काउंसल को हिरासत में लेने या अभियुक्त की रिहाई पर शर्तों की मांग करने से नहीं रोकता है।

क्रिमिनल कोड की धारा 515(1) से लेकर 515(2.03) स्पष्ट करती हैं कि, सीमित अपवादों के अलावा, जमानत की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त को रिहाई के आदेश पर बिना किसी शर्त के तब तक रिहा करना चाहिए जब तक कि क्राउन काउंसल अभियुक्त को हिरासत में लेने का कारण न बताए। अथवा सशर्त रिहाई उचित है।

क्रिमिनल कोड की धारा 515(4.1) से (4.3) के तहत जिन शर्तों को लगाया जाना चाहिए या उन पर विचार किया जाना चाहिए, और एक शर्त है कि अभियुक्त अदालत में उपस्थित होता है, के अलावा क्राउन काउंसल को केवल उन शर्तों का प्रस्ताव करना चाहिए जो में निर्धारित वैधानिक आधारों को संबोधित करने के उद्देश्य से हैं-धारा 515(10)। किन शर्तों, यदि कोई हों, का निर्णय लेने में, क्राउन काउंसल को अभियुक्त की व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्रस्तावित शर्तों के संचयी प्रभाव पर विचार करना चाहिए। [7]

सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करना और न्याय के प्रशासन में विश्वास बनाए रखना

कुछ परिस्थितियों में क्राउन काउंसल के लिए जमानत के लिए अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। उदाहरण के लिए, नीचे सूचीबद्ध नीतियां पीड़ितों और गवाहों सहित जनता की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देती हैं:

- *बाल पीड़ित और गवाह* (CHI 1)
- *अंतरंग साथी हिंसा* (IPV 1)
- *यौन अपराध* के पीड़ित - *वयस्क पीड़ित* (SEX 1)
- *कमजोर पीड़ित और गवाह* (VUL 1)

बार-बार अपराध करने वालों, विशेष रूप से बार-बार हिंसक अपराधियों के संबंध में जनता की सुरक्षा या सुरक्षा भी चिंता का विषय है।

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, बार-बार होने वाले हिंसक अपराधी में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास एक या एक से अधिक हाल ही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध (*आपराधिक संहिता* के भाग VIII के तहत) या किसी हथियार से जुड़े अपराध (जैसा कि *आपराधिक संहिता* की धारा 2 में परिभाषित किया गया है) शामिल

---

[7] *R v Zora*, 2020 SCC 14 at paras 25 and 89

है।). जब बार-बार हिंसक अपराधी पर व्यक्ति के खिलाफ अपराध या हथियार से जुड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो क्राउन काउंसल को उनकी हिरासत की मांग करनी चाहिए, जब तक कि वे संतुष्ट न हों, सभी परिस्थितियों के संबंध में, कि अभियुक्त की रिहाई से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है जमानत शर्तों द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है।

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पर विचार करते हुए, क्राउन काउंसल को ऐसे किसी भी कारक पर विचार करना चाहिए जो अभियुक्त को हिरासत में लेने के पक्ष में हो सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- गिरफ़्तारी के समय, अभियुक्त पर एक या एक से अधिक बकाया आपराधिक आरोप थे, जिसमें व्यक्ति के विरुद्ध अपराध या हथियार से जुड़े अपराध का आरोप लगाया गया था
- कथित अपराध को अंजाम देते समय, अभियुक्त ने कथित रूप से निवारक पहचान की शर्त का उल्लंघन किया है, या आपराधिक संहिता के तहत लगाए गए हथियार निषेध का उल्लंघन किया है
- *क्रिमिनल कोड* की धारा 515(6) में रिवर्स ऑनस प्रावधान

पुलिस द्वारा जारी उपक्रमों की समीक्षा

पुलिस के पास *क्रिमिनल कोड* की धारा 498(1)(c), 499(b), या 503(1.1) के तहत एक अभियुक्त को एक उपक्रम पर रिहा करने की शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करने में, पुलिस को आपराधिक संहिता की धारा 493.1 के द्वारा आवश्यक है कि वह आरोपी को जल्द से जल्द उचित अवसर पर रिहा करने पर प्राथमिक विचार करे, कम से कम कठिन शर्तों पर जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और आरोपी के लिए उचित रूप से व्यावहारिक हैं का अनुपालन करें।

क्राउन काउंसल को रिपोर्ट प्राप्त होने पर, क्राउन काउंसल को पुलिस द्वारा जारी किए गए किसी भी उपक्रम की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। जब पुलिस द्वारा जारी उपक्रम की शर्तें पीड़ित, पीड़ित के परिवार, गवाहों और जनता की सुरक्षा के लिए अप्रवर्तनीय या अपर्याप्त हों, तो क्राउन काउंसल को रिहाई आदेश के लिए धारा 502(2) के तहत एक वारंट का अनुरोध करना चाहिए या न्याय के लिए आवेदन करना चाहिए। अलग शर्तें। जब कम प्रतिबंधात्मक शर्तें पर्याप्त होंगी, तो क्राउन काउंसल को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या धारा 502(2) के तहत बदलाव उचित है।

जमानत के कथित उल्लंघनों का आरोप निर्धारण

जब ज़मानत का उल्लंघन अदालत की जानबूझकर अवज्ञा के बराबर होता है या जनता या पीड़ित सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करता है, तो यह उचित प्रतिक्रिया की मांग करता है। हालांकि, अभियुक्त के बदलते या चुनौतीपूर्ण जीवन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कई उल्लंघन होते हैं, जो शर्तों के साथ सख्त अनुपालन को कठिन बना सकते हैं। बाद के प्रकार के उल्लंघन अक्सर अदालत या जनता या पीड़ित सुरक्षा की जानबूझकर अवहेलना के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं नहीं उठाते हैं।

जैसा कि *चार्ज असेसमेंट गाइडलाइंस* (CHA 1) में रेखांकित किया गया है, भले ही साक्ष्य परीक्षण पूरा हो गया

हो, न्याय की आवश्यकता नहीं है कि हर साबित अपराध पर मुकदमा चलाया जाए। अभियोजन को उन मामलों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए जिनमें आपराधिक न्याय प्रणाली की सभी उपलब्ध स्वीकृतियों के साथ पूरी शक्ति की आवश्यकता होती है। जब यह आरोप लगाया जाता है कि एक अभियुक्त ने ज़मानत की शर्त का उल्लंघन किया है, तो क्राउन काउंसल को ज़मानत के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली सूचना देने से पहले सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

जमानत के कथित उल्लंघन के लिए अभियोजन पक्ष के उचित विकल्पों में शामिल हो सकते हैं:

- धारा 515(10) के प्रयोजनों के लिए कथित रूप से उल्लंघन की स्थिति की निरंतर आवश्यकता की समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार संशोधन करना या उसमें बदलाव करना
- *क्रिमिनल कोड* की धारा 524 के तहत जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करना
- धारा 725(1)(c) के अनुसार, समान तथ्यों से उत्पन्न एक मूल अपराध की सजा पर परिस्थितियों के हिस्से के रूप में जमानत के उल्लंघन की परिस्थितियों का आरोप लगाना

धारा 145(4) या 145(5) के तहत एक आरोप केवल तभी स्वीकृत किया जाना चाहिए जब जमानत समीक्षा और निवारण के माध्यम से उपलब्ध उपाय अपर्याप्त हों।[8]

इस दृष्टिकोण का एक अपवाद *अंतरंग साथी हिंसा* (IPV 1) नीति द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में है: "न्यायालय के आदेश का उल्लंघन भविष्य की हिंसा के लिए एक पहचाना गया जोखिम कारक है, इसलिए क्राउन काउंसल के लिए आरोपों को मंजूरी देने पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जब उचित हो, जमानत के उल्लंघन के लिए ”।

गरीब और कमजोर व्यक्ति

गरीब और कमजोर आरोपी व्यक्ति, जिनके पास या तो परिवार और दोस्तों या वित्तीय साधनों का समर्थन नेटवर्क नहीं है, जमानत तक पहुंचने में कम सक्षम हैं।[9] ज़मानत के बारे में निर्णय लेते समय, *आपराधिक संहिता* की धारा 493.2(बी) के लिए एक न्यायाधीश को अभियुक्तों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो एक कमजोर आबादी से संबंधित हैं जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अधिक प्रतिनिधित्व है और जो रिहाई प्राप्त करने में वंचित है।

क्राउन काउंसल को ऐसी किसी भी स्थिति की मांग नहीं करनी चाहिए जो किसी अभियुक्त की विशेष जीवन परिस्थितियों (जैसे, गरीबी, बेघर, शराब या नशीली दवाओं की लत, मानसिक या शारीरिक बीमारी, या अक्षमता) को आपराधिक बनाने, या दंडित करने की प्रवृत्ति रखती हो। एक शर्त तभी उपयुक्त होगी जब अभियुक्त के विशिष्ट जोखिमों को संबोधित करना आवश्यक हो।[10]

---

[8] *R v Zora,* 2020 SCC 14 at para 70
[9] *R v Zora,* 2020 SCC 14 at para 92
[10] *R v Zora,* 2020 SCC 14 at para 92

मूल निवासी

कई सरकारी आयोगों और रिपोर्टों के साथ-साथ कैनेडा के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने यह माना है कि मूल निवासियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला भेदभाव, चाहे खुले तौर पर नस्लवादी व्यवहार या सांस्कृतिक रूप से अनुचित प्रथाओं के परिणामस्वरूप, आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी हिस्सों तक फैला हुआ है।

कैनेडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास ने कम शैक्षिक प्राप्ति, कम आय, उच्च बेरोजगारी, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या की उच्च दर और मूल निवासियों के लिए उच्च स्तर की कैद में अनुवाद किया है।

असमान रूप से उच्च स्तर का कारावास भी मूल निवासियों के खिलाफ पूर्वाग्रह और एक संस्थागत दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है जो उन्हें जमानत देने से इनकार करने के लिए अधिक इच्छुक है। [11]

इसके अलावा, मूल निवासियों के उत्पीड़न की दर, विशेष रूप से मूल निवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए, गैर-मूल निवासियों की तुलना में काफी अधिक है। [12]

कैनेडा में मूल निवासियों के लिए उपनिवेशवाद के निरंतर परिणाम एक मूल निवासी आरोपी से जुड़े जमानत के विचार के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं। इन परिणामों को "मूल निवासी लोगों को प्रभावित करने वाले अद्वितीय प्रणालीगत और पृष्ठभूमि कारकों के साथ-साथ उनके मौलिक रूप से भिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और विश्व विचारों के लिए लेखांकन द्वारा उपचारित किया जाना चाहिए।" [13]

मूल निवासी आरोपी व्यक्ति - जमानत विचार

जब क्राउन काउंसल अभियुक्त की पृष्ठभूमि के बारे में अनिश्चित हो, तो उन्हें अभियुक्त, बचाव पक्ष के वकील, या अदालत से जल्द से जल्द उचित अवसर पर पूछताछ करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त एक मूल निवासी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। क्राउन काउंसल को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जानकारी फ़ाइल में दर्ज है।

क्राउन काउंसल को पूरे अभियोजन के दौरान प्रदान की गई किसी भी जानकारी पर विचार करना चाहिए, जो अद्वितीय प्रणालीगत या पृष्ठभूमि कारकों से संबंधित हो सकती है, जिसने अदालत के समक्ष एक मूल निवासी अभियुक्त को लाने में भूमिका निभाई हो और उन कारकों के साथ-साथ उपनिवेशवाद के निरंतर परिणामों पर प्रभाव पड़ेगा। मूल निवासी अभियुक्तों की आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ चल रही बातचीत।

बेरोज़गारी, आवास की अस्थिरता, महत्वपूर्ण वित्तीय साधनों के बिना ज़मानत, कथित अपराध से असंबद्ध मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या, या उस समुदाय से पर्याप्त संबंध की कमी जिसमें अपराध कथित रूप से घटित हुआ हो, जैसे कारक *सरकार बनाम ग्लेड्यू*[14] में पहचाने गए अद्वितीय प्रणालीगत या पृष्ठभूमि कारकों

---

[11] *R v Ipeelee*, 2012 SCC 13

[12] *Victimization of Aboriginal People in Canada, 2014*, Statistics Canada, 2016

[13] *Ewert v Canada*, 2018 SCC 30 at paras 57-58; *R v Barton*, 2019 SCC 33 at paras 198-200

[14] *R v Gladue* [1999] 1 S.C.R. 688

को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसलिए, मूल निवासी अभियुक्तों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने के साथ, क्राउन काउंसल को ज़मानत और सभी ज़मानत कार्यवाहियों के संबंध में सभी निर्णयों में सैद्धांतिक संयम बरतना चाहिए। क्राउन काउंसल को मूल निवासी अभियुक्त की हिरासत की मांग केवल तभी करनी चाहिए जब:

- अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने का अभियुक्त का इतिहास कोई उचित संभावना नहीं छोड़ता है कि किसी भी प्रकार की रिहाई मामले को उसके गुण-दोषों के आधार पर समाप्त करने में सक्षम बनाएगी; या
- कथित अपराध हिंसा या शारीरिक नुकसान का है, या जब जमानत पर रिहा होने से पीड़ित, गवाह, या जनता की सुरक्षा या सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम होगा

मूल निवासी अभियुक्तों की संभावित रिहाई योजनाओं का आकलन करने में, क्राउन काउंसल:

- पीड़ितों, गवाहों, या जनता की सुरक्षा या सुरक्षा के लिए एक जोखिम को संबोधित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक शर्तों की तलाश करनी चाहिए या, अभियुक्त के अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के पिछले इतिहास को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले की योग्यता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा
- उस समुदाय की दूरदर्शिता पर विचार करना चाहिए जिसमें अभियुक्त रहता है और साथ ही उस समुदाय के भीतर अद्वितीय सांस्कृतिक संबंधों या परंपराओं पर विचार करना चाहिए, और अन्य समुदायों में अन्यथा उपयुक्त जमानत शर्तों को लागू करने के लिए ये चुनौतियां पेश कर सकती हैं
- ज़मानत के प्रयोग में सैद्धान्तिक संयम बरतना चाहिए

क्रिमिनल कोड की धारा 493.2(ए) में ज़मानत का फ़ैसला करते समय मूल निवासी अभियुक्तों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। जमानत की सभी कार्यवाहियों में, क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल निवासी अभियुक्त की परिस्थितियों के बारे में उनके लिए उपलब्ध सभी उचित जानकारी भी अदालत को उपलब्ध कराई जाए।